



सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 377] मई विसं, बुधवार, नवम्बर 24, 1977 अग्राहायण 3, 1899

No. 377] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 24, 1977/AGRAHAYANA 3, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATIONS

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 24th November 1977

G.S.R. 714(E).—In exercise of the powers conferred by section 37 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government hereby

(2267)

makes the following rules further to amend the Central Excise Rules, 1944, namely —

1 (1) These rules may be called the Central Excise (27th Amendment) Rules, 1977.

(2) They shall come into force on the 25th day of November, 1977

2 In the Central Excise Rules, 1944, in Chapter V, after rule 49, the following rule shall be inserted, namely:—

“49A Collection of duty leviable on cellulosic spun yarn and cotton yarn along with the duty on cotton fabrics—

Where a manufacturer,—

(i) who manufactures cellulosic spun yarn falling under Item No 18III(1) of the First Schedule to the Act, or cotton yarn falling under Item No 18A(1) of the said First Schedule, or both, and uses the whole or part of the yarn so manufactured in the manufacture of cotton fabrics in his own factory, or

(ii) who being a composite mill, brings such yarn under rule 96E or rule 96EE, as the case may be, from outside for the purpose of manufacture of cotton fabrics in his own factory,

makes an application to the Collector in this behalf, shall, on such application being granted by the Collector, pay the duty leviable on such cellulosic spun yarn and such cotton yarn along with the duty on such cotton fabrics in the manner prescribed in rule 52, subject to the following conditions, namely.—

(1) when the cotton fabrics are cleared grey (unprocessed), the yarn duty payable shall be—

(a) the appropriate duty payable on such cellulosic spun yarn or cotton yarn, or both, as the case may be; *plus*

(b) one and a half per cent of the duty payable on such cellulosic spun yarn, or cotton yarn, or both, as the case may be, by way of interest on the amount of yarn duty;

(2) when the cotton fabrics are cleared after processing, the yarn duty payable shall be—

(a) the appropriate duty payable on such cellulosic spun yarn, or cotton yarn, or both, as the case may be, *plus*

(b) three per cent, of the duty payable on such cellulosic spun yarn, or cotton yarn, or both, as the case may be, by way of interest on the amount of yarn duty.

Explanation—For the purposes of this rule, “composite mill” means a manufacturer who is engaged in spinning of cotton yarn or weaving or processing of cotton fabrics with the aid of power and has a proprietary interest in at least two of such manufacturing activities.”

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचनाएँ

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 1977

सा० का० नि० 714(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् —

1. (1) इन नियमों का नाम, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (27वां संशोधन) नियम, 1977 है।

(2) ये 25 नवम्बर, 1977 को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अध्याय 5 में, नियम 49 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतर्स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“49क. सैल्यूलोसी कटे हुए सूत और सूती सूत पर, सूती फैब्रिक पर शुल्क के साथ-साथ उद्ग्रहणीय शुल्क का संग्रहण—

जहाँ कोई विनिर्माता,—

- (i) जो अधिनियम के प्रथम अनुसूची की मद सं० 18III (i) के अंतर्गत सम्मिलित सैल्यूलोसी कटे सूत का या उक्त प्रथम अनुसूची की मद सं० 18क(i) के अंतर्गत सम्मिलित सूती सूत का या दोनों का विनिर्माण करता है और इस प्रकार विनिर्मित मंपूर्ण सूत या उसके किसी भाग का उपयोग अपने ही कारखाने में सूती फैब्रिक के विनिर्माण में करता है, अथवा
- (ii) जो कि संयुक्त मिल है, अपने ही कारखाने में सूती फैब्रिक के विनिर्माण के प्रयोजन के लिए, यथास्थिति, नियम 96 ड या 96 डड के अधीन बाहर से ऐसा सूत लाता है,

क्लकटर को इस निमित्त आवेदन करता है, वहाँ क्लकटर द्वारा ऐसे आवेदन को मंजूर किए जाने पर ऐसे सैल्यूलोसी कटे हुए सूत और ऐसे सूती सूत पर उद्ग्रहणीय शुल्क का संदाय, नियम 52 में विहित रीति में ऐसे सूती फैब्रिक पर शुल्क के साथ-साथ, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए करेगा, अर्थात् :—

- (1) जब सूती फैब्रिक की निकासी बिना धुलाई किए हुए (अप्रसंस्कृत) रूप में की जाती है तो सूत पर देय शुल्क निम्नलिखित होगा—
- (क) ऐसा समुचित शुल्क होगा जो ऐसे सैल्यूलोसी कटे हुए सूत या सूती सूत या दोनों पर देय हो; और इसके अतिरिक्त
- (ख) सूत पर शुल्क की रकम पर ब्याज के रूप में शुल्क का डेढ़ प्रतिशत जो ऐसे सैल्यूलोसी कटे सूत या सूती सूत या दोनों पर देय हो ;

(2) जब सूती फैब्रिक की निकासी प्रसंस्करण के पश्चात् की जाती है तब सूत पर देय शुल्क निम्नलिखित होगा—

(क) ऐसा समुचित शुल्क होगा जो ऐसे सैल्यूलोसी कते हुए सूत या सूती सूत या दोनों पर देय हो; और इसके अतिरिक्त

(ख) सूत पर शुल्क की रकम पर ब्याज के रूप में शुल्क का तीन प्रतिशत जो ऐसे सैल्यूलोसी कते सूत या सूती सूत या दोनों पर देय हो।

स्पष्टीकरण.—इन नियमों के प्रयोजन के लिए, “संयुक्त मिल” से ऐसा विनिर्माता अभिप्रेत है जो पावर की सहायता से सूती सूत की कताई में या सूती फैब्रिक की बुनाई या प्रसंस्करण में लगा हुआ है और जिसका कम से कम ऐसे दो विनिर्माण कार्यकलापों में साम्प्रतिक हित है।”

[मं० 322/77]

G.S.R. 715(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-section (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (56 of 1957), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No 226/77-Central Excises, dated the 15th July, 1977, namely:—

In the said notification, in the first proviso—

(1) for clause (i), the following clause shall be substituted, namely:—

“(1) in the case of handloom fabrics, when processed by an independent processor approved in this behalf by the Government of India on the recommendation of the Handloom Development Commissioner, the appropriate rate of duty as specified in the Table shall be reduced by sixty per cent of such rate, subject to the following conditions, namely:—

(a) in the case of cotton fabrics in which the average count of yarn is 41s or more when cleared after processing but without printing, the rate of duty leviable shall be five per cent *ad valorem*;

(b) in the case of cotton fabrics, other than those covered by condition (a) above, such reduction from such rate shall not exceed six per cent *ad valorem* ;”;

(2) in clause (ii), the following words “for the purpose of such processing”, the words “for the purpose of development of handlooms” shall be substituted;

(3) for clause (iii), the following clause shall be substituted, namely:—

“(iii) in the case of powerloom fabrics [other than those covered by clause (ia)] and in the case of handloom fabrics [other than those covered by clause (i) and clause (ii)] when processed by an independent processor, the appropriate rate of duty as specified in the Table shall be reduced by thirty per cent, of such rate, subject to the following conditions, namely —

(a) in the case of cotton fabrics in which the average count of yarn is 41a or more when cleared after processing but without printing, the rate of duty leviable shall be eight per cent *ad valorem*;

(b) in the case of cotton fabrics, other than those covered by condition (a) above, such reduction from such rate shall not exceed three per cent *ad valorem* ”

2. This notification shall come into force on the 25th day of November, 1977.

[No. 323/77]

सा०का०मि० 715(अ) —केन्द्रीय सरकार, अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व के माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उपधारा (3) के साथ पठित, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बैकिंग विभाग) की अधिसूचना सं० 226/77—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 15 जुलाई, 1977 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्—

उक्त अधिसूचना के प्रथम परन्तुक में, (1) खण्ड (i) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्—

“(i) हथकरघा के फैब्रिकों की दशा में, जब उसका प्रसंस्करण ऐसे स्वतंत्र प्रसंस्करण-कर्ता द्वारा किया जाता है जो भारत हथकरघा विकास आयुक्त की सिफारिश पर भारत सरकार द्वारा इस निमित्त अनुमोदित किया गया हो, मारणी में यथाविनिर्दिष्ट शुल्क की समुचित दर ऐसी दर का साठ प्रतिशत, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, कम कर दी जाएगी, अर्थात्—

(क) ऐसे सूती फैब्रिक की दशा में जिसमें सूत का काउंट 41 या अधिक है, तब जब उसकी निकामी प्रसंस्करण के बाद किन्तु छपाई के बिना, की जाए, उद्ग्रहणीय शुल्क की दर, मूल्य का पांच प्रतिशत होगी,

(ख) ऊपर शर्त (क) के अन्तर्गत सम्मिलित सूती फैब्रिक में भिन्न सूती फैब्रिक की दशा में, ऐसी दर से, ऐसी कमी मूल्य के छह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी;”;

(2) खण्ड (i) में “ऐसे प्रसंस्करण के प्रयोजन के लिए” शब्दों के स्थान पर “हथकरघा के विकास के प्रयोजन के लिए” शब्द रखे जाएंगे;

(3) खण्ड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्:—

“(ii) पावर करघा फैब्रिकों की दशा में [खण्ड (ii) क) में सम्मिलित फैब्रिकों से भिन्न] और हथकरघा फैब्रिकों की दशा में [खण्ड (i) और (ii) के अन्तर्गत सम्मिलित फैब्रिक से भिन्न] जब उनका प्रसंस्करण स्वतंत्र प्रसंस्करणकर्ता द्वारा किया जाए, मारणी में, यथाविनिर्दिष्ट, शुल्क की समुचित दर ऐसी दर का तीस प्रतिशत, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, कम कर दी जाएगी, अर्थात्—

(क) ऐसे सूती फैब्रिक की दशा में जिसमें सूत का काउंट 41 या अधिक है, तब जब उनकी निकामी प्रसंस्करण के बाद किन्तु छपाई के बिना की जाए, उद्ग्रहणीय शुल्क की दर, मूल्य का आठ प्रतिशत होगी,

(ख) ऊपर शर्त (क) के अन्तर्गत सम्मिलित सूती फैब्रिक में भिन्न सूती फैब्रिक की दशा में, ऐसी दर से, ऐसी कमी मूल्य के तीन प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।”।

2. यह अधिसूचना 25 नवम्बर, 1977 को प्रवृत्त होगी।

G.S.R. 716(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-section (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (38 of 1957), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Department of Revenue and Banking No. 136/77-Central Excises, dated the 18th June, 1977, namely:—

In the said notification, in the first proviso—

(1) for clause (1), the following clause shall be substituted, namely:—

“(1) in the case of handloom fabrics when processed by an independent processor, approved in this behalf by the Government of India on the recommendation of the Handloom Development Commissioner, the appropriate rate of duty as specified in the Table shall be reduced by sixty per cent of such rate, subject to the following conditions, namely:—

(a) in the case of cotton fabrics in which the average count of yarn is 41s or more when cleared after processing but without printing, the rate of duty leviable shall be five per cent. *ad valorem*,

(b) in the case of cotton fabrics, other than those covered by condition (a) above, such reduction from such rate shall not exceed six per cent *ad valorem*”;

(2) in clause (1a), for the words “for the purpose of such processing of”, the words “for the purpose of development of handlooms,” shall be substituted;

(3) for clause (1), the following clause shall be substituted, namely.—

“(1) in the case of powerloom fabrics, [other than those covered by clause (1b)] and in the case of handloom fabrics, [other than those covered by clause (1) and clause (1a)], when processed by an independent processor, the appropriate rate of duty as specified in the Table shall be reduced by thirty per cent of such rate, subject to the following conditions, namely:—

(a) in the case of cotton fabrics in which the average count of yarn is 41s or more when cleared after processing but without printing, the rate of duty leviable shall be eight per cent. *ad valorem*;

(b) in the case of cotton fabrics, other than those covered by condition (a) above, such reduction from such rate shall not exceed three per cent *ad valorem*”

2 This notification shall come into force on the 25th day of November, 1977

[No. 324/77]

सा०का०नि० 716(अ)—केन्द्रीय सरकार, अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व के माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उपधारा (3) के साथ पठित, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बैंकिंग विभाग) की अधिसूचना सं० 136/77-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 18 जून, 1977 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्—

उक्त अधिसूचना के प्रथम परन्तुक में, (1) खण्ड (i) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्—

(i) हथकरघा के फैब्रिकों की दशा में, जब उसका प्रसंस्करण ऐसे स्वतंत्र प्रसंस्करण कर्ता द्वारा किया जाता है जो हथकरघा विकास आयुक्त की सिफारिश पर भारत सरकार द्वारा इस निमित्त अनुमोदित किया गया हो, सारणी में

यथाविनिर्दिष्ट शुल्क की समुचित दर ऐसी दर का साठ प्रतिशत, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, कम कर दी जाएगी, अर्थात् —

- (क) ऐसे सूती फैब्रिक की दशा में जिसमें सूत का काउंट 41क या अधिक है, तब जब उसकी निकामी प्रसंस्करण के बाद किन्तु छपाई के बिना, की जाए, उद्ग्रहणीय शुल्क की दर, मूल्य का पांच प्रतिशत होगी ,
 - (ख) ऊपर शर्त (क) के अन्तर्गत सम्मिलित सूती फैब्रिक में भिन्न सूती फैब्रिक की दशा में, ऐसी दर से, ऐसी कमी मूल्य के छह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, ”,
 - (2) खण्ड (i) में “ऐसे प्रसंस्करण के प्रयोजन के लिए” शब्दों के स्थान पर “हथकरघा के विकास के प्रयोजन के लिए” शब्द रखे जाएंगे ।
 - (3) खण्ड (ii) क स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् —
- “(ii) पावर करघा फैब्रिकों की दशा में खण्ड (ix) में सम्मिलित फैब्रिकों से भिन्न एक [और हथकरघा फैब्रिकों की दशा में खण्ड 7(i) और खण्ड (i) के अन्तर्गत सम्मिलित फैब्रिक से भिन्न जब उनका प्रसंस्करण स्वतन्त्र प्रसंस्करणकर्ता द्वारा किया जाए, सारणी में, यथाविनिर्दिष्ट, शुल्क की समुचित दर ऐसी दर का तीस प्रतिशत, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहने हुए, कम कर दी जाएगी, अर्थात्:—
- (क) ऐसी सूती फैब्रिक की दशा में जिसमें सूत का काउंट 41 या अधिक है, तब जब उनकी निकामी प्रसंस्करण के बाद किन्तु छपाई के बाद, की जाए, उद्ग्रहणीय शुल्क की दर, मूल्य का आठ प्रतिशत होगी;
 - (ख) ऊपर शर्त (क) के अन्तर्गत सम्मिलित सूती फैब्रिक में भिन्न सूती फैब्रिक की दशा में, ऐसी दर से, ऐसी कमी मूल्य के तीन प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।” ।

2 यह अधिसूचना 25 नवम्बर, 1977 को प्रवृत्त होगी ।”

[सं० 324/77]

GSR 717(E) In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944 read with sub-section (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act 1957 (58 of 1957), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Department of Revenue and Banking, No 137/77-Central Excises, dated the 18th June, 1977, namely:—

In the said notification, the following shall be inserted at the end, namely —

“Provided that cotton fabrics when printed by roller printing machine, without the aid of power or steam shall be exempt from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of one-third of the duty of excise leviable thereon when processed by an independent processor.”

Provided further that the amount of duty so levied shall be apportioned in the ratio of 75 : 25 between the duty leviable under the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) and the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), respectively

Explanation—For the purposes of this notification “independent processor” means a manufacturer who is engaged exclusively in the processing of cloth with the aid of power and who has no proprietary interest in any factory engaged in the spinning of yarn or weaving of cotton fabrics’

2 This notification shall come into force on the 28th day of November, 1977

[No 325/77]

सांकांनि० 717(अ) —केन्द्रीय सरकार, अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व के माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उपधारा (3) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग की अधिसूचना सं० 137/77—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 18 जन, 1977 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् —

उक्त अधिसूचना में, अंत में, निम्नलिखित अंत स्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

“परन्तु जब सूती फैब्रिक की छपाई पावर या भाप की सहायता के बिना रोलर छपाई मशीन से की जाए, तब वे उन पर उद्ग्रहणीय उत्पाद-शुल्क के उतने भाग से छूट प्राप्त होंगे जो यदि उनका प्रसंस्करण किसी स्वतंत्र प्रसंस्करणकर्ता द्वारा किया जाता तब उन पर उद्ग्रहणीय उत्पाद शुल्क से एक तिहाई से अधिक हो :

परन्तु यह और कि इस प्रकार उद्ग्रहणीय शुल्क की रकम केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) तथा अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व के माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) के अधीन उद्ग्रहणीय शुल्क के बीच कमणः 75 : 25 के अनुपात में प्रभाजित की जाएगी ।

स्पष्टीकरण.—इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिये “स्वतंत्र प्रसंस्करणकर्ता” से ऐसा विनिर्माता अभिप्रेत है, जो पावर की सहायता से वस्त्र के प्रसंस्करण में अनन्य रूप से लगा हुआ है और जिसका सूत की कटाई या सूती फैब्रिकों की बुनाई में लगे हुए किसी कारखाने में कोई साम्प्रतिक हिता नहीं है ।” ।

2 यह अधिसूचना 28 नवम्बर, 1977 को प्रवृत्त होगी ।

[सं० 325/77]

G.S.R. 718(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-section (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act 1957 (58 of 1957), the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 228/77-Central Excises, dated the 15th July, 1977

2, This notification shall come into force on the 25th day of November, 1977.

[No 326/77]

LAJJA RAM, Dy Secy.

सांकांमि० 718 (अ).—केन्द्रीय सरकार, अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व के माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उपधारा (3) के साथ पठित, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मन्त्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 228/77—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 15 जुलाई, 1977 को इस अधिसूचना द्वारा विखंडित करती है।

2. यह अधिसूचना 25 नवम्बर, 1977 को प्रवृत्त होगी।

[सं० 326/77]

लज्जा राम, उप-सचिव।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD,
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977

